PRGI : APHIN/26/A3657

पेन पॉवर

हिंदी दैनिक समाचार पत्र

वर्ष - 1 अंक - 38 बुदवार, अगस्त 19, 2026 *विशाखापट्टनम* संपादकः गंट्यादा अप्पाराव पृष्ठों. 4 मूल्य. 1रु

नगरपालिकाओं में बीसी को 34% आरक्षणः सीएम चंद्रबाबू नायडू

(पेन पॉवर न्यूज):
अमरावतीः आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि गठबंधन सरकार पिछड़े वर्गों (ठबे) के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आंध्र प्रदेश विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि नगरपालिकाओं में बीसी को 34: आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीसी को 34: आरक्षण देना केवल चुनावी वादा नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक सिद्धांत का हिस्सा है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सरकार केवल वादे करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें लागू करके भी दिखा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा बीसी आरक्षण के मामले में किए गए अन्याय को सुधारने के लिए विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित कर निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनावों में गठबंधन की इस स्तर की जीत के पीछे बीसी समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने कहा कि 94: स्ट्राइक रेट और 57: वोट शेयर हासिल होना बीसी के समर्थन और नेतृत्व पर उनके विश्वास के कारण संभव हुआ।
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्होंने, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और भाजपा नेताओं ने चुनाव से पहले ही बीसी को न्याय दिलाने का निर्णय लिया था।
उन्होंने कहा कि बीसी को राजनीतिक रूप से अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों में 34: और शहरी स्थानीय निकायों में 33. 33: आरक्षण लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन दोनों प्रावधानों से संबंधित नियम कानूनों में पहले से मौजूद हैं।
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों में मेयर और नगरपालिका अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता द्वारा कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में 28 जिला परिषदों के गठन की संभावना है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार बीसी आरक्षण की रक्षा करने में विफल रही। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार का यह निर्णय एक बार फिर साबित करता है कि वह पिछड़े वर्गों के साथ मजबूती से खड़ी है।
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि टीडीपी के गठन से पहले राजनीति में सामंतवाद का प्रभाव था। उन्होंने कहा कि एन.टी. रामाराव (एनटीआर) के मुख्यमंत्री बनने के बाद सभी वर्गों को सत्ता में भागीदारी देने की सोच के साथ आगे बढ़े। एनटीआर ने एर्रम नायडू, के.ई. कृष्णमूर्ति, चिंताकायला अय्यन्नापात्रुडु, यनमाला रामकृष्णुडु और तेलंगाना के देवेंदर गौड़ जैसे नेताओं को राजनीति में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चंद्रबाबू नायडू ने कहा।
चंद्रबाबू नायडू ने याद दिलाया कि 1995 में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बीसी के लिए 34: आरक्षण लागू किया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि 2019 में सरकार बदलने के बाद बीसी के साथ अन्याय हुआ। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार द्वारा जारी जी.ओ. एमएस नंबर 176 को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और अदालत ने उसे रद्द कर दिया था। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीसी का आरक्षण 34: से घटाकर 24.5: कर दिया गया।
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बीसी को राजनीतिक महत्व देने के मामले में टीडीपी से पहले और टीडीपी के बाद की राजनीति पर चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बीसी को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना उनकी सरकार का लक्ष्य है।

आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में बीसी को 34% आरक्षणः मंत्री सविता

(पेन पॉवर न्यूज):
अमरावती, 18 अगस्तः
आंध्र प्रदेश विधानसभा में स्थानीय स्वशासन के माध्यम से पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने के मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा हुई। मंत्री सविता ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि बीसी को अवसर देना, प्रतिनिधित्व देना और उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना सरकार का दायित्व है। उन्होंने कहा कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में बीसी को 34: आरक्षण देने को आज राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जगन सरकार के कार्यकाल में बीसी को हर क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ा और वाईएसआरसीपी सरकार की नीतियों के कारण बीसी आरक्षण के मामले में अन्याय हुआ।
मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 34: और शहरी क्षेत्रों में 33: आरक्षण लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एन.टी. रामाराव (एनटीआर) ने बीसी के विकास के लिए टीडीपी की स्थापना की थी और मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू एनटीआर की प्रेरणा से शासन चला रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 1994 में पहली बार बीसी के लिए 34: आरक्षण लागू किया गया था। मंत्री ने कहा कि 2019 में सत्ता में आई वाईएसआरसीपी सरकार ने इस आरक्षण को घटाकर 24: कर दिया। उन्होंने दावा किया कि आरक्षण में 10: की कटौती के कारण बीसी समुदाय 16,800 पदों से वंचित हो गया।
मंत्री सविता ने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बीसी को एक बार फिर राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दिलाने का निर्णय लिया है और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में 34: आरक्षण दिया जाएगा।
बीसी को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और मंत्री नारा लोकेश को सविता ने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के सत्ता में लौटने से बीसी समुदाय के लिए एक बार फिर अच्छे दिन आए हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने सत्ता में आने के बाद पहले बजट में 39,000 करोड़, दूसरे बजट में 47,000 करोड़ और तीसरे बजट में 51,000 करोड़ बीसी के लिए आवंटित किए हैं। उन्होंने बताया कि सत्ता में आते ही स्वर्णकारों के लिए एक अलग निगम स्थापित किया गया।
उन्होंने कहा कि विधायिकाओं में बीसी को 33: आरक्षण देने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। इसके अलावा, नामित पदों की नियुक्तियों में बीसी को 34: आरक्षण देने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

डीएससी पर चर्चा के लिए बुलाने पर भी बच रहे हैं जगनः केंद्रीय मंत्री

(पेन पॉवर न्यूज):
कुरनूल, 18 अगस्तः केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने वाईएसआरसीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी पर तंज कसते हुए कहा कि मंत्री नारा लोकेश द्वारा विधानसभा में डीएससी–2025 पर चर्चा के लिए आमंत्रित किए जाने के बावजूद जगन इससे बच रहे हैं। राममोहन नायडू ने जगन से लोकेश की चुनौती स्वीकार कर विधानसभा में चर्चा के लिए आने को कहा। मंगलवार को कुरनूल के निकट ओरवाकल में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकेश मेगा डीएससी पर विधानसभा में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा में आने पर उनकी कथित साजिश उजागर होने के डर से जगन चर्चा में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जगन गठबंधन सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर अपनी राजनीतिक मौजूदगी बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि जगन ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षकों को शराब की दुकानों के बाहर खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को देखते ही जगन के मन में गुस्सा और द्वेष पैदा होता है।
राममोहन नायडू ने कहा कि मेगा डीएससी के माध्यम से बिना किसी अनियमितता के पूरी पारदर्शिता के साथ हजारों शिक्षक पदों पर भर्ती की गई है। उन्होंने दावा किया कि जितने शिक्षक पद किसी पिछली सरकार ने नहीं भरे, उससे कहीं अधिक पद उनकी सरकार ने भरे हैं। उन्होंने राज्य में निवेश लाने के लिए मंत्री नारा लोकेश के प्रयासों की भी सराहना की और कहा कि केवल दो वर्षों में आंध्र प्रदेश में अप्रत्याशित विकास हुआ है।
बाद में केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने कुरनूल के निकट ओरवाकल मंडल के पालकोलनु में स्थापित किए जा रहे ड्रोन सिटी में विभिन्न ड्रोन कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि ड्रोन सिटी को न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। देश में करीब 6 लाख ड्रोन की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में केवल लगभग 40 हजार ड्रोन ही उपलब्ध हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू कुरनूल जिले में ड्रोन सिटी परियोजना पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू की विजन से प्रभावित होकर ड्रोन कंपनियां आगे आ रही हैं। ओरवाकल में 600 एकड़ में ड्रोन सिटी स्थापित की जाएगी, जहां ड्रोन निर्माण, उत्पादन और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहां स्थापित होने वाली कंपनियों को राज्य सरकार की ओर से रियायतें और प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन की क्षमता और उपयोगिता को पहचाना है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि भारतीय तकनीक का इस्तेमाल कर देश में ही ड्रोन बनाए जाएं और उन्हें विदेशों में निर्यात किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने विदेशों से ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से इस ड्रोन सिटी की स्थापना की जा रही है। यह भारत की पहली बड़ी एकीकृत ड्रोन सिटी होगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न ड्रोन कंपनियों के साथ समीक्षा बैठकें कर उनकी आवश्यकताओं और सुझावों को जाना जाएगा। कार्यक्रम में करीब 150 ड्रोन कंपनियों के प्रतिनिधियों के शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने खुशी व्यक्त की।

पिछली सरकार के कार्यकाल में बीसी के साथ अन्याय हुआ, टीडीपी ही बनी सहाराः मंत्री अच्चेनायडू

(पेन पॉवर न्यूज):
अमरावती, 18 अगस्तः मंत्री के. अच्चेनायडू ने कहा कि पिछड़े वर्गों को न्याय केवल तेलुगु देशम पार्टी के शासन में ही मिला। मंगलवार को आंध्र प्रदेश विधानसभा में बीसी सशक्तीकरण और आरक्षण पर चर्चा के दौरान मंत्री ने कहा कि एन.टी. रामाराव द्वारा टीडीपी की स्थापना के बाद कमजोर वर्गों के लोगों को विधानसभा में भेजा गया और स्थानीय निकायों में 20% आरक्षण दिया गया।
उन्होंने याद दिलाया कि 1995 में मुख्यमंत्री रहते हुए एन. चंद्रबाबू नायडू ने बीसी के लिए 34% आरक्षण लागू किया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून में बदलाव करना हो तो उसमें आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए था। अच्चेनायडू ने आरोप लगाया कि जगन के सत्ता में आने के बाद कमजोर वर्गों पर हमले और दमन किए गए। उन्होंने कहा कि टीडीपी के गठन के समय से ही बीसी समुदाय पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहा है और इसी कारण वाईएसआरसीपी ने बीसी समुदाय को निशाना बनाया।
मंत्री ने पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उसने कमजोर वर्गों के समर्थन की बात करते हुए आरक्षण बढ़ाया, लेकिन कानून में संशोधन करने के बजाय नया सरकारी आदेश जारी कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर वाईएसआरसीपी समर्थक के माध्यम से अदालत में मामला दायर कराया गया। उन्होंने कहा कि अदालत में झटका लगने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया गया, जिससे बीसी समुदाय के साथ अन्याय हुआ। अच्चेनायडू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने आज विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित कर स्थानीय निकायों में बीसी को आरक्षण देने के मुद्दे पर चर्चा की और निर्णय लिया। उन्होंने कमजोर वर्गों से आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी का समर्थन करने की अपील की।

मंदिरों की नौकरियों में जोनल व्यवस्था नहीं, मेरिट को प्राथमिकताः मंत्री अनम रामनारायण रेड्डी

(पेन पॉवर न्यूज):
अमरावती, 18 अगस्तः मंत्री अनम रामनारायण रेड्डी ने स्पष्ट किया कि मंदिरों में अर्चकों, वेद पंडितों, परिचारकों और अन्य धार्मिक कर्मचारियों की नियुक्तियों में कोई जोनल व्यवस्था लागू नहीं है। आंध्र प्रदेश विधानसभा में मंदिरों में नियुक्तियों से संबंधित सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि प्रमुख मंदिरों में अर्चकों और वेद पंडितों की नियुक्तियों में रायलसीमा के साथ अन्याय होने की कोई शिकायत सरकार के संज्ञान में नहीं आई है।
उन्होंने बताया कि हाल ही में भरे गए 344 पदों में से 172 पद रायलसीमा क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों में भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीशैलम, महानंदी, श्रीकालहस्ती और कनिपकम जैसे प्रमुख मंदिरों में रिक्त पदों को निर्धारित नियमों के अनुसार अधिसूचना जारी कर भरा जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि उम्मीदवार के क्षेत्र की परवाह किए बिना वेद एवं आगम ज्ञान, योग्यता, प्रतिभा और मेरिट को ही प्राथमिकता दी गई। उन्होंने बताया कि प्रमुख मंदिरों के वेद और आगम पंडितों को चयन समितियों में सदस्य नियुक्त कर इंटरव्यू कराए गए। उन्होंने कहा कि लगभग 1,400 उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल हुए। प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी होने के कारण एक या दो अंकों के अंतर से भी चयन हुआ। अनम ने बताया कि रायलसीमा क्षेत्र से 1,431 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें पात्र पाए गए 172 उम्मीदवारों को अवसर मिला। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का चयन वेद, संस्कृत और आगम ज्ञान के आधार पर किया गया।
मंत्री ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया को वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित किया गया। उन्होंने बताया कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग उम्मीदवारों को भी दिखाई गई। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वण वेद से संबंधित नियुक्तियों में भी योग्यता, वेद ज्ञान और मेरिट के आधार पर ही चयन किया गया।
अनम ने बताया कि रायलसीमा जोन–4 के अंतर्गत प्रमुख मंदिरों में 440 पद हैं।

सीएम चंद्रबाबू और मंत्री लोकेश ने निर्मला सीतारमण को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

अमरावतीः आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने निर्मला सीतारमण के अच्छे स्वास्थ्य, सुख–समृद्धि और दीर्घायु की कामना की। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि वह अपार ऊर्जा और समर्पण के साथ देश की प्रगति को आगे बढ़ाती रहेंगी। चंद्रबाबू और लोकेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं दीं।

सीएम चंद्रबाबू की एक्स पोस्ट

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने कहा, "माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हृदय से जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं आपके स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। आप उसी समर्पण और अथक ऊर्जा के साथ देश की प्रगति का मार्गदर्शन करती रहें और आने वाले समय में कई और सफलताएं हासिल करें, ऐसी मेरी कामना है।"

मंत्री लोकेश की शुभकामनाएं

मंत्री नारा लोकेश ने भी निर्मला सीतारमण को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने देश के लिए केंद्रीय मंत्री द्वारा दी जा रही विशिष्ट सेवाएं आगे भी जारी रहने की कामना की। उन्होंने निर्मला सीतारमण के अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और अधिक ऊर्जा के लिए भगवान से प्रार्थना की। लोकेश ने उनके आने वाले वर्ष में और अधिक सफलताएं हासिल करने की कामना की।

नगरपालिकाओं के विलय की प्रक्रिया स्थानीय निकाय चुनावों के बादः सीएम चंद्रबाबू

(पेन पॉवर न्यूज):
अमरावती, 18 अगस्तः बढ़ती महंगाई को देखते हुए मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। राज्य मंत्रिमंडल के एजेंडे के सभी मुद्दे पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने मंत्रियों को सोशल मीडिया पर आ रही नकारात्मक टिप्पणियों का मजबूती से जवाब देने की सलाह दी।
मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि यदि अक्टूबर तक स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराए गए, तो राज्य को ध्12,150 करोड़ के शहरी स्थानीय निकाय (न्स्ठ) फंड से वंचित होने का खतरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक विचाराधीन 23 नगरपालिकाओं के विलय की प्रक्रिया बाद में देखी जा सकती है। पहले सभी नगरपालिकाओं में चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने समिति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शराब के ब्रांड अनुचित या अजीब नामों के साथ बाजार में न आएं।
चंद्रबाबू नायडू ने अवैध रूप से कंटेनरों में रेत ले जाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी स्पष्ट निर्देश दिए।

संपादकीय

आधार हमारा... करोड़ों उनके!

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देश की आर्थिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने, कर चोरी पर अंकुश लगाने और व्यावसायिक लेन–देन को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से लागू किया गया एक महत्वपूर्ण सुधार है। डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से व्यावसायिक लेन–देन की निगरानी की संभावनाएं बढ़ी हैं। इसके बावजूद, इसी डिजिटल व्यवस्था की खामियों का फायदा उठाकर कुछ जालसाज करोड़ों रुपये के जीएसटी घोटालों को अंजाम दे रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। इससे भी अधिक खतरनाक बात यह है कि आम लोगों के आधार, पैन, बैंक खातों और बायोमेट्रिक विवरण का इस्तेमाल कर उन्हें फर्जी कंपनियों का मालिक दिखाया जा रहा है। हाल में सामने आई घटनाओं से पता चलता है कि जालसाजों की रणनीति कितनी सुनियोजित हो चुकी है। रिपोर्टों के अनुसार गरीबों, छोटे व्यापारियों, फल विक्रेताओं और लॉरी चालकों को थोड़े पैसे देने का लालच देकर उनके निजी दस्तावेज लिए जा रहे हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर कंपनियां पंजीकृत की जा रही हैं, जीएसटी नंबर हासिल किए जा रहे हैं, फर्जी खरीद–बिक्री के बिल बनाए जा रहे हैं और उन्हीं बिलों के आधार पर भारी मात्रा में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया जा रहा है। पीड़ित को वास्तविक स्थिति की जानकारी हुए बिना ही उसके नाम पर करोड़ों रुपये के लेन–देन रिकॉर्ड में दर्ज हो जाते हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल यही हैकृअगर किसी आम व्यक्ति के नाम पर करोड़ों रुपये का कारोबार हो रहा है, तो संबंधित प्रणालियों को उस पर संदेह क्यों नहीं होता?

यदि कोई व्यक्ति अब तक छोटे स्तर पर आजीविका कमाता रहा हो और अचानक करोड़ों रुपये के टर्नओवर वाली व्यावसायिक संस्था का मालिक बन जाए, तो क्या इसे सामान्य घटना माना जा सकता है? यदि किसी लॉरी चालक या छोटे व्यापारी के नाम पर कुछ ही महीनों में करोड़ों रुपये की खरीद–बिक्री दर्ज हो जाए, तो क्या डिजिटल प्रणाली यह पता नहीं लगा सकती कि इन लेन–देन के पीछे वास्तविक कारोबार है या नहीं? ऐसे असामान्य लेन–देन की पहले से पहचान करने के लिए जीएसटी प्रणाली में जोखिम–आधारित चेतावनी व्यवस्था की आवश्यकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी व्यवस्था का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके तहत व्यापारी अपनी खरीद पर चुकाए गए कर को बिक्री पर देय कर से समायोजित कर सकता है। वास्तविक कारोबार के लिए यह कर भार कम करने की एक प्रभावी व्यवस्था है। लेकिन यदि वास्तविक खरीद हुए बिना फर्जी चालान बनाकर आईटीसी हासिल किया जाने लगे, तो इससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो सकता है। एक फर्जी बिल दूसरे फर्जी बिल का आधार बन सकता है और अंततः करोड़ों रुपये के कर घोटाले में बदल सकता है। ऐसी स्थिति में आम लोगों की पहचान संबंधी जानकारी का जालसाजों के हाथों में पहुंचना और भी खतरनाक हो जाता है। एक बार आधार, पैन, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक जानकारी दूसरों के हाथ लग जाए तो उसके दुरुपयोग को रोकना मुश्किल हो जाता है। थोड़े पैसे के लिए अपने दस्तावेज किसी को सौंपने वाला व्यक्ति बाद में अपने नाम पर हुए करोड़ों रुपये के लेन–देन का जवाब देने के लिए मजबूर हो सकता है। ऐसे मामलों में आम लोगों को दोषी ठहराना उचित नहीं है। जालसाज कम डिजिटल जागरूकता रखने वाले लोगों को निशाना बनाते हैं और उनकी आर्थिक जरूरतों का फायदा उठाते हैं। "हम आपको कुछ पैसे देंगे", "आपके दस्तावेज चाहिए", "आपके नाम पर कंपनी रजिस्टर करेंगे" या "आपका बैंक खाता इस्तेमाल करेंगे" जैसी बातों से लोग ठगे जा सकते हैं। लेकिन केवल इस आधार पर कि किसी व्यक्ति ने लापरवाही से अपने दस्तावेज दे दिए, पूरी जिम्मेदारी उसी पर डालना न्यायसंगत नहीं है। असली सवाल यह होना चाहिएकृअपराध किसने किया? लाभ किसने उठाया? कंपनी कौन चला रहा था? लेन–देन कौन कर रहा था? इन सवालों के जवाब तलाशना जरूरी है। इस मामले में सरकार की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना आवश्यक है। लेकिन इसके साथ–साथ सुरक्षा मानकों को भी मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि सरल व्यवस्था का जालसाज दुरुपयोग न कर सकें। यदि नई जीएसटी पंजीकृत संस्था अचानक असामान्य रूप से बड़ा टर्नओवर दिखाती है, तो स्वतः जोखिम चेतावनी जारी होनी चाहिए। डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से कारोबार का स्थान, बैंक लेन–देन, चालान के पैटर्न और खरीद–बिक्री के आपसी संबंधों की जांच की जानी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पेशे, आय और पिछले कारोबारी इतिहास के बिल्कुल विपरीत उसके नाम पर करोड़ों रुपये के लेन–देन दिखाई दें, तो उन्हें सामान्य लेन–देन मानने के बजाय पहले उनका सत्यापन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी छोटे स्तर के मजदूर या ड्राइवर के नाम पर अचानक घ्20 करोड़ या घ्30 करोड़ का टर्नओवर दर्ज हो जाए, तो प्रणाली में विशेष जांच शुरू होनी चाहिए। यदि कारोबार वास्तविक है तो उस व्यापारी को कोई परेशानी नहीं होगीय और यदि कंपनी फर्जी है तो शुरुआती चरण में ही घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है।

जीएसटी सुधार का उद्देश्य ईमानदारी से कर चुकाने वाले व्यापारियों के लिए मुश्किलें पैदा करना नहीं, बल्कि कर चोरी पर रोक लगाना है। इसलिए भविष्य में चार पहलुओं को समान प्राथमिकता दी जानी चाहिएकृफर्जी कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, फर्जी चालानों की त्वरित जांच, संदिग्ध आईटीसी दावों पर तत्काल रोक और पहचान के दुरुपयोग का शिकार हुए आम नागरिकों को संरक्षण। तकनीक अपराधियों का हथियार नहीं बननी चाहिए। उसे आम नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच बनना चाहिए।यदि किसी व्यक्ति के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला होता है, तो प्रणाली को सबसे पहले यह पूछना चाहिएकृ"यह अपराध किसने किया?", न कि केवल यहकृ"यह नाम किसका है?" यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि आम नागरिक का आधार नंबर जालसाज के हाथों में हथियार न बन जाए, उसके नाम पर करोड़ों रुपये के फर्जी बिल न बनाए जाएं और अंततः वही व्यक्ति आरोपी बनकर खड़ा न हो जाए। जीएसटी व्यवस्था में सुधार के अगले चरण का लक्ष्य केवल कर संग्रह नहीं, बल्कि आम नागरिकों को कर घोटालों से सुरक्षा देना भी होना चाहिए।

क्या यह निरर्थक युद्ध कभी खत्म होगा?

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध फिलहाल खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले जून में हुआ अंतरिम शांति समझौता सोमवार को समाप्त हो गया। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना था और 60 दिनों तक सैन्य कार्रवाइयां रोकनी थीं। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। इसके बजाय दोनों ओर से एक–दूसरे पर हमले जारी हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमले भी नहीं रुके हैं। मंगलवार को एक वाणिज्यिक जहाज पर अज्ञात ड्रोन हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। ऐसे हालात में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भले ही होर्मुज जलडमरूमध्य को अपने नियंत्रण में लेने की धमकी दे रहे हों, लेकिन ईरान इससे जरा भी भयभीत नहीं है। ईरान लगातार कह रहा है कि अंततः होर्मुज जलडमरूमध्य पर उसका ही प्रभुत्व रहेगा। इसके अलावा, होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर जहाजों की आवाजाही को लेकर ईरान का ओमान के साथ समझौता करना भी ट्रंप को रास नहीं आ रहा है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ओमान होर्मुज के मामले में हस्तक्षेप करता है तो अमेरिका बमबारी करेगा। दूसरी ओर, ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के सहयोगी जापान, फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई देश ट्रंप का साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं।

हाल ही में दक्षिण कोरिया के भी ट्रंप के प्रस्ताव से दूरी बनाने के बाद अमेरिका उत्तर कोरिया के साथ सुलह की दिशा में कदम बढ़ाता दिखाई दे रहा है। ट्रंप उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की प्रशंसा करते हुए उन्हें अपना अच्छा मित्र बता रहे हैं। दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या भी ट्रंप ने आधी कर दी है। ऐसे में यह समझना मुश्किल हो गया है कि ट्रंप कब किसे गले लगाएंगे और किसे दूर कर देंगे।इसी पृष्ठभूमि में खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप परमाणु हथियारों पर नियंत्रण के नाम पर ईरान के खिलाफ परमाणु हमले की तैयारी कर रहे हैं। यदि महाशक्ति अमेरिका परमाणु हमला शुरू करता है तो पूरी दुनिया युद्ध के मैदान में बदल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के गंभीर संकट में फंसने का खतरा पैदा हो सकता है।

इस बीच ट्रंप की युद्ध नीति का अमेरिका में ही भारी विरोध बढ़ रहा है। ईरान के साथ युद्ध के लिए समुद्र में डेरा डाले अमेरिकी नौसेना के जवान निराशा और हताशा में डूबे हुए हैं। अमेरिका के सामने चुनौतियां केवल सैन्य आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स तक सीमित नहीं हैं। अमेरिकी नौसेना किस तरह की कठिनाइयों का सामना कर रही है, इसका अंदाजा यूएसएस अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत की स्थिति से लगाया जा सकता है। करीब नौ महीने से समुद्र में तैनात इस युद्धपोत पर मौजूद नौसैनिक मानसिक और शारीरिक रूप से भारी तनाव झेल रहे हैं। इस जहाज पर लगभग 5,000 नौसैनिक तैनात हैं। कई महीनों से अपने घरेलू बंदरगाह लौटने का अवसर नहीं मिलना, परिवारों से दूर रहना, आवश्यक वस्तुओं की कमी, पीने के पानी और स्वच्छता से जुड़ी समस्याएं तथा लगातार चल रहे युद्ध अभियानों ने उनका मनोबल बुरी तरह प्रभावित किया है। कुछ रिपोर्टों में कुछ नौसैनिकों द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने की बात भी सामने आई है।

हालांकि ट्रंप प्रशासन इन समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है। नौसेना नेतृत्व अपने जवानों के धैर्य की सराहना करते हुए कह रहा है कि उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता उपलब्ध करा जा रही है। लेकिन नौसैनिकों के परिवारों का आरोप है कि सैन्य नेतृत्व जहाज की वास्तविक समस्याओं को कम करके दिखा रहा है। वे सैन्य नेतृत्व से जहाज की परिस्थितियों का स्वयं निरीक्षण करने की मांग कर रहे हैं। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका का 326 दिनों का मिशन सबसे लंबा मिशन रहा था। उसी तरह अब अब्राहम लिंकन भी लंबे समय से समुद्र में तैनात है। ईरान के खिलाफ युद्ध को बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के और बार–बार अपने उद्देश्यों को बदलते हुए ट्रंप प्रशासन किस तरह आगे बढ़ा रहा है, यह बताने के लिए लिंकन पोत की स्थिति ही पर्याप्त है। इस असहनीय स्थिति के कारण हाल ही में इस पोत के दो नौसैनिकों ने समुद्र में छलांग लगाकर अपनी जान गंवा दी। इसके बावजूद ट्रंप को इसका कोई खास असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका में बड़े पैमाने पर युद्ध–विरोधी जन आंदोलन हुए थे। अंततः अमेरिकी सरकार को उस युद्ध से पीछे हटना पड़ा था। लेकिन ट्रंप प्रशासन इन अनुभवों से कोई सबक सीखता दिखाई नहीं दे रहा है। इस हाइपर–कनेक्टेड दुनिया में सत्ता में बैठे लोगों के लिए जनता की आंखों पर पट्टी बांधना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। ईरान युद्ध के कारण ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। रूस में भी कुछ ऐसी ही स्थिति दिखाई दे रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे युद्ध को लेकर रूस की जनता में असंतोष दिखाई दे रहा है। रूस में आगामी संसदीय चुनावों से पहले एकमात्र युद्ध–विरोधी पार्टी मानी जाने वाली 'याब्लोको' पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन क्या किसी पार्टी पर प्रतिबंध लगाने मात्र से जनता के विरोध की लहर को रोका जा सकता है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी ऐसी ही तानाशाही कार्रवाइयों के साथ युद्धोन्माद को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसी आलोचनाएं हो रही हैं। जब ऐसे निरर्थक युद्धों में लगातार युवा अपनी जान गंवा रहे हों, तब सत्ता में बैठे लोगों को परिस्थितियों के अनुसार अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। अन्यथा वही तानाशाही और अहंकार अंततः महाशक्ति अमेरिका के लिए भी गंभीर परेशानियां खड़ी कर सकता है।

क्या सवाल करने वाला हर व्यक्ति 'दिमागी नक्सल' है?

क्या सवाल करने वाला हर व्यक्ति 'दिमागी नक्सल' है?
क्या दिमाग रखने वाला हर इंसान 'दिमागी नक्सल' है?
क्या सोचने वाला हर नागरिक देश के लिए खतरा है?
क्या सवाल उठाने वाली हर आवाज पर नक्सलवाद की मुहर लगा दी जाएगी?
ये सवाल आज भारतीय लोकतंत्र के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं।

सवाल करना लोकतंत्र की प्राणवायु है। सोचना मानव प्रगति की पहली सीढ़ी है। असहमति लोकतंत्र की दुश्मन नहीं, बल्कि सत्ता को जवाबदेह बनाने की ताकत है। सरकार की नीतियों की आलोचना करना देश–विरोधी होना नहीं है। जनता की समस्याओं पर सवाल उठाना देश को कमजोर करना नहीं है।

लेकिन अगर सवाल करने की इसी शक्ति को एक शब्द के जरिए संदिग्ध बनाने की कोशिश शुरू हो जाए, तो लोकतांत्रिक समाज को सतर्क होना चाहिए।

सरकार से सवाल करना क्या नक्सलवाद है?

15 अगस्त को लाल किले से दिए गए स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सशस्त्र नक्सलवाद देश में कमजोर हो चुका है और माओवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले 'दिमागी नक्सलों' से एक नया खतरा पैदा हो रहा है। सरकार का कहना है कि इस शब्द का इस्तेमाल सरकार की आलोचना करने वाले हर व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि माओवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले बुद्धिजीवी वर्ग के लिए किया गया है। फिर भी असहमति को नक्सलवाद से जोड़ने की आशंका स्वाभाविक है।

यहीं से असली सवाल शुरू होता है।

सरकार से सवाल करना क्या नक्सलवाद है?

छात्रों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करना क्या नक्सलवाद है?

परीक्षाओं में अनियमितताओं पर सवाल उठाना क्या नक्सलवाद है?

नौकरी मांगना क्या नक्सलवाद है?

सत्ता को जवाबदेह बनाना क्या नक्सलवाद है?

इन सवालों का जवाब जनता को नहीं... सरकार को देना चाहिए।

वक्त है छात्रों के गुस्से को सुनने का

देश में हाल के दिनों में छात्रों का असंतोष किस स्तर तक पहुंच गया है, यह दिल्ली से लेकर झारखंड तक दिखाई दे रहा है। परीक्षाओं की विश्वसनीयता, पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं और रोजगार को लेकर अनिश्चितताकृइन सबने युवाओं में गुस्सा बढ़ाया है।

NEET UG 2026 विवाद के बाद छात्रों का आंदोलन इतना तेज हुआ कि अंततः केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक बात पहुंच गई। इस्तीफा देते समय उन्होंने छात्रों के भविष्य, देश की एकता और परिस्थितियों का देश–विरोधी ताकतों द्वारा फायदा उठाए जाने जैसे मुद्दों का उल्लेख किया। लेकिन सवाल यह है कि छात्रों का आंदोलन इतना गंभीर होने की नौबत क्यों आई? उनकी शिकायतों का समाधान पहले ही क्यों नहीं किया जा सका? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं।

झारखंड में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। 24 दिनों तक चले छात्र आंदोलन के बाद सरकार ने श्रेब–ब्ळऌ परीक्षा रद्द करने के साथ–साथ आउटसोर्सिंग संस्था द्वारा आयोजित अन्य भर्ती परीक्षाओं, उनके परिणामों और चयन प्रक्रियाओं को लेकर भी कार्रवाई करने का फैसला किया। अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए गए। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात केवल एक है।

जब छात्र सड़कों पर उतरकर सवाल पूछें, तो यह तलाशने के बजाय कि उनके पीछे कौन है, यह तलाशना ज्यादा जरूरी है कि उनके सवाल में सच्चाई कितनी है।

क्या परीक्षा में गड़बड़ी हुई?

अगर हुई तो जिम्मेदार कौन है?

व्यवस्था में कमी कहां है?

अगर छात्र को नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कैसे होगी?

भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए क्या सुधार किए जाने चाहिए?

सरकार से पूछे जाने वाले असली सवाल यही हैं।

क्या यह ध्यान भटकाने की राजनीति है?

यहीं 'दिमागी नक्सल' शब्द को लेकर एक और सवाल पैदा होता है। जब देश का युवा परीक्षा, रोजगार, भविष्य और सरकारी नीतियों पर सवाल कर रहा हो, तब उसके सवालों का जवाब देने के बजाय यह पूछना शुरू कर दिया जाए कि छात्रों के पीछे कौन है, तो असली समस्या के भटक जाने का खतरा पैदा होता है।

किसी भी समस्या के सामने आने पर सरकार को उसका समाधान करने के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन समस्या को पीछे धकेलने के लिए कोई नया राजनीतिक शब्द सामने लाया जाए तो पूरी बहस उसी शब्द के इर्द–गिर्द घूमने लगती है। तब छात्र का सवाल दिखाई नहीं देता। परीक्षा व्यवस्था की खामी दिखाई नहीं देती। नौकरी की तलाश कर रहे युवा की पीड़ा दिखाई नहीं देती।

हाल ही में सोशल मीडिया पर 'क्पउंहप छं॰स च्ंतजल' नाम से एक मंच दिखाई देना भी इस घटनाक्रम की दिलचस्प प्रतिक्रिया है। इसे आधिकारिक रूप से पंजीकृत राजनीतिक दल कहने का कोई आधार नहीं है, लेकिन युवाओं द्वारा इस नाम को व्यंग्यात्मक प्रतिरोध के रूप में अपनाना जरूर ध्यान देने योग्य है।

'मुझे दिमागी नक्सल कह रहे हो? तो इसी नाम से मैं तुमसे सवाल करूंगा'कृइसमें विरोध और चुनौती की आवाज सुनाई देती है।

आज का युवा केवल मतदाता नहीं है। वह अपनी राजनीतिक भाषा खुद बना रहा है। मीम के जरिए प्रतिक्रिया देता है। व्यंग्य के जरिए विरोध करता है। सत्ता की भाषा को ही वापस लेकर उसी भाषा में सत्ता से सवाल करता है।

आज 'दिमागी नक्सल'... कल कौन?

आज सरकार 'दिमागी नक्सल' शब्द का एक निश्चित और वैचारिक अर्थ बता रही है। लेकिन कल?

सरकारी नीतियों पर सवाल उठाने वाला छात्र?

भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला कर्मचारी?

जमीन के मुद्दे पर संघर्ष करने वाला किसान?

जनसमस्या को लेकर आंदोलन करने वाला नागरिक?

सरकारी नीतियों की आलोचना करने वाला पत्रकार? सरकार के फैसले पर सवाल उठाने वाला बुद्धिजीवी? इन सभी को एक ही नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। सबको एक ही खांचे में डालने को लेकर आशंका लोकतंत्र में स्वाभाविक सतर्कता है। सावधान रहना जरूरी है।

सशस्त्र नक्सलवाद से मुकाबला करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जंगल में होने वाला सशस्त्र विद्रोह अलग है और जनसमुदाय के बीच उठने वाला सवाल अलग।

अगर किसी छात्र के हाथ में किताब हो और वह सवाल पूछे?

अगर किसी पत्रकार के हाथ में कलम हो और वह सवाल पूछे?

अगर कोई वैज्ञानिक अपने शोध के आधार पर सरकार की नीति की आलोचना करे?

अगर कोई नागरिक अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर उतरे?

उसे जवाब चाहिए। लाठी नहीं। टियर गैस नहीं। वाटर कैनन नहीं। मुकदमे नहीं। जेल नहीं!

सवाल करने वाला दिमाग ही देश की ताकत है!

भारत को दुनिया में शीर्ष स्थान तक पहुंचाना है तो हमें सवाल न करने वाले छात्र नहीं चाहिए। सोचने से डरने वाले बुद्धिजीवी नहीं चाहिए। मुंह बंद रखने वाले पत्रकार नहीं चाहिए।

हमें चाहिएकृसोचने वाला युवा। सवाल करने वाले छात्र। नए आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक। सच्चाई तलाशने वाले पत्रकार। समाज को आगे ले जाने वाले बुद्धिजीवी। सत्ता को जवाबदेह बनाने वाले नागरिक।

देश को महान बनाने के लिए केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है। नए विचार, नए आविष्कार, आलोचना को स्वीकार करने की संस्कृति और असहमति का सम्मान करने वाला लोकतंत्र भी देश की ताकत हैं।

सरकार अस्थायी है। देश स्थायी है। सरकार गलती करे तो देश की ओर से उस पर सवाल उठाना जनता का अधिकार है। सत्ता को जवाबदेह बनाना देश–विरोधी गतिविधि नहीं, बल्कि नागरिक का कर्तव्य है।

आखिर सवाल सिर्फ एक है 'दिमागी नक्सल' कौन है?

सोचने वाला?

सवाल करने वाला?

आलोचना करने वाला?

असहमति व्यक्त करने वाला?

या फिर वह राजनीति, जो सवाल का जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वाले को ही दोषी ठहराती है?

लोकतंत्र में खतरनाक सवाल नहीं है।

खतरनाक है वह सत्ता, जो सवाल का जवाब देने से इनकार करती है।

क्योंकि...

दिमाग को डराया नहीं जा सकता।

विचार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

सवाल को जेल में नहीं डाला जा सकता।

सवाल करने वाली आवाज लोकतंत्र की दुश्मन नहींकृ बल्कि लोकतंत्र की प्रहरी है!

आश्रम विद्यालयों में गोबरधन बायोगैस संयंत्र

रामपचोडवरम, पेन पावर, 18 अगस्त: पोलावरम जिला कलेक्टर के. दिनेश कुमार ने जिले के सभी सरकारी आश्रम विद्यालयों में गोबरधन बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

मंगलवार को आईटीडीए कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन आश्रम विद्यालयों में बायोगैस संयंत्रों की आवश्यकता है, उनकी पहचान कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने गांवों में पेयजल टैंकों की नियमित सफाई और उसकी तस्वीरों सहित रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने गांवों में प्रतिदिन स्वच्छता अभियान चलाने, गीले और सूखे कचरे को अलग–अलग एकत्र कर वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने तथा स्वच्छता वाहनों का प्रभावी उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के रूप में पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन शॉप कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया।

उन्होंने पर्यटन क्षेत्रों में कचरा फैलाने से रोकने, लंबित कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने और बेहतर स्वच्छता सेवाओं के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।

18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं के लिए विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान

रामपचोड़वरम, पेन पावर, 18 अगस्त: पोलावरम जिला कलेक्टर के. दिनेश कुमार ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पात्र युवाओं को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कलेक्टर ने बताया कि जिले के सभी 399 मतदान केंद्रों पर बीएलओ की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि 8,514 मतदाता अभी मैपिंग से बाहर हैं। वहीं 16,182 मतदाताओं के लिए नोटिस तैयार किए गए हैं और 15,537 को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कलेक्टर ने बताया कि मृतक, अनुपस्थित और दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित मतदाताओं के संबंध में पूरी जांच के बाद

अपात्र नामों को मतदाता सूची से हटाया जाएगा। राजनीतिक दलों से मतदाता सूची संबंधी सुझाव और आपत्तियां निर्धारित समय सीमा में अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के अंत तक मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

नवीनीकरण कार्यों की गुणवत्ता से समझौता नहीं: कलेक्टर

गुंटूर, पेन पावर, 18 अगस्त: जिला कलेक्टर सी.एम. साईकांत वर्मा ने आवासीय एवं शैक्षणिक संस्थानों में 'चेंज' कार्यक्रम के तहत चल रहे नवीनीकरण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मंगलवार को अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने बताया कि जिलेभर में 36 आवासीय एवं शैक्षणिक संस्थानों में नवीनीकरण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने आवश्यक सुविधाओं के साथ विद्यार्थियों एवं निवासियों के लिए सुखद एवं बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। अधिकारियों को हर 10 लोगों के लिए एक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ–साथ वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा उत्पादन और उचित कचरा प्रबंधन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। बैठक में समाज कल्याण, ठब् कल्याण, जनजातीय कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, ।च शिक्षा एवं कल्याण अवसंरचना विकास निगम, सड़क एवं भवन तथा छम्क्ब।च विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

नशा, रैगिंग और अपराध रोकथाम पर जागरूकता कार्यक्रम

विशाखापत्तनम, पेन पावर, 18 अगस्त: विग्नान्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एंटी–रैगिंग सेल के तत्वावधान में नशे के दुरुपयोग, रैगिंग और अपराध रोकथाम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। साउथ सब–डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त वाई. श्रीनिवास राव ने छात्रों को संबोधित करते हुए नशे के दुरुपयोग, रैगिंग और आपराधिक गतिविधियों के कानूनी, सामाजिक एवं व्यक्तिगत दुष्परिणामों के बारे में बताया। उन्होंने जिम्मेदार व्यवहार अपनाने, अपराध की रोकथाम के उपायों पर ध्यान देने तथा आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों से सहायता लेने पर जोर दिया। कार्यक्रम में एसआई रामचंद्र राव भी उपस्थित रहे। प्राचार्य डॉ. जे. सुधाकर,

रेक्टर डॉ. वी. मधुसूदन राव और डीन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डॉ. च. हरि गोविंद राव ने इस पहल की सराहना की और छात्रों से सुरक्षित, सम्मानजनक एवं अनुशासित परिसर वातावरण बनाए रखने का आग्रह किया। कार्यक्रम का समन्वय एंटी–रैगिंग सेल के प्रभारी एम. मदन शेखर ने किया।

बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य

विजयवाड़ा, पेन पावर, 18 अगस्त: जिला कलेक्टर डॉ. जी. लक्ष्मीश ने अभिभावकों से बच्चों के अनिवार्य आधार बायोमेट्रिक अपडेट को समय पर पूरा कराने की अपील की। 5–7 वर्ष और 15–17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट 30 सितंबर 2026 तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। जिले में कुल 68,654 बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट लंबित है।

विजयवाड़ा कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक में कलेक्टर ने आधार पंजीकरण और अपडेट की समीक्षा की। उन्होंने स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और जूनियर कॉलेजों के माध्यम से बच्चों व अभिभावकों में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश

दिए। उन्होंने आधार सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए कलेक्ट्रेट, आरडीओ और तहसीलदार कार्यालयों में स्थायी आधार केंद्र स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए।

हर शिकायत का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें: कलेक्टर

ओंगोल, पेन पावर, 18 अगस्त: प्रकाशम जिला कलेक्टर पी. राजाबाबू ने अधिकारियों को च्ळत् के माध्यम से दर्ज प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंगलवार को जिला एवं मंडल स्तर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कहा कि शिकायतों के दोबारा दर्ज होने का मुख्य कारण उनका उचित समाधान नहीं होना है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना समस्या का वास्तविक समाधान किए शिकायतों को निपटाया हुआ दर्ज करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने स्वच्छता, कचरा संग्रहण,

स्कूलों की साफ–सफाई और गड्ढामुक्त सड़कों पर विशेष निगरानी रखने को कहा। प्टत् फीडबैक में इन क्षेत्रों में जनता की संतुष्टि का स्तर कम पाया गया है। कलेक्टर ने पेयजल की कमी को रोकने के लिए पहले से उपाय करने, खराब पड़े बोरवेलों की मरम्मत कराने तथा स्कूलों और कल्याण छात्रावासों में वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने SIR के तहत 1.96 लाख मतदाताओं को जारी नोटिस संबंधित मतदाताओं तक क्षेत्र स्तर पर पहुंचाने को भी कहा। अधिकारियों को प्रभावी निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई के जरिए सरकारी सेवाओं के प्रति जनता की संतुष्टि बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने EVM और VVPAT वेयरहाउस का निरीक्षण किया

काकीनाडा, पेन पावर, 18 अगस्त: काकीनाडा जिला कलेक्टर एम.एन. हरेंद्र प्रसाद ने मंगलवार को कलेक्टोरेट के पास स्थित EVM और VVPAT वेयरहाउस का राजस्व, पुलिस और चुनाव अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया।

कलेक्टर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और VVPAT इकाइयों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि EVM वेयरहाउस का हर महीने राजस्व, पुलिस और चुनाव अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाता है तथा निरीक्षण रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जाती है।

निरीक्षण में जिला राजस्व अधिकारी डॉ. टी. टिप्पेनायक, काकीनाडा अर्बन तहसीलदार वी. जितेंद्र, कलेक्टोरेट चुनाव अधीक्षक एम. जगन्नाथम समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए।

स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों में जुटने के निर्देश

काकीनाडा, पेन पावर, 18 अगस्त: काकीनाडा जिला कलेक्टर एम.एन. हरेंद्र प्रसाद ने जिले में स्थानीय निकाय चुनावों के सफल संचालन के लिए अधिकारियों को व्यापक तैयारियां करने के निर्देश दिए।

मंगलवार को कलेक्टोरेट में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सरकार के निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत, ZPTC और MPTC चुनावों की तैयारियां करने को कहा।

उन्होंने 18 से 22 अगस्त तक SC, ST और BC मतदाताओं का घर–घर जाकर सत्यापन करने तथा 7 सितंबर को अंतिम सूची

प्रकाशित करने के निर्देश दिए। मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर 31 अगस्त तक अंतिम सूची तैयार करने को कहा गया।

कलेक्टर ने 22 अगस्त तक डच्ब् और च्ब् मतदाता सूचियां प्रकाशित करने तथा 3 सितंबर को तुनी, पेड्डापुरम, समालकोटा, गोल्लप्रोलु और येलेश्वरम नगरपालिकाओं की वार्डवार प्रारूप मतदाता सूचियां जारी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ चुनाव संबंधी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने और चुनावों का पारदर्शी तरीके से संचालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

कश्मीरा शाह ने शादियों और बेवफाई पर जाहिर की निराशा, कहा- क्या अब भी होता है सच्चा प्यार

अभिनेत्री कश्मीरा शाह ने 'लाफ्टर शेफ्स' के सभी सीजन में अपनी मजेदार पर्सनैलिटी से दर्शकों के दिलों में दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। सोमवार को अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के जरिए शादियों और बेवफाई पर निराशा जाहिर की। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें आसमान में दिल के आकार का धुंध है। अभिनेत्री ने अपने पोस्ट के जरिए सवाल उठाया है कि क्या 'सच्चा प्यार' अब भी होता है। कश्मीरा ने लिखा, क्या यही सच्चा प्यार होता है? क्या ये सच में होता है? क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है कि उसके लिए पैसे खर्च करे और उसे स्पेशल महसूस कराए? ऐसा प्यार कहां मिलता है? और वो इंसान कौन है? शादियां टूटते और लोगों को धोखा देते देखकर मेरा भरोसा हिल गया है। लगता है मुझे हकीकत की थोड़ी सी झलक चाहिए।

गौरतलब है कि कश्मीरा का यह पोस्ट उनके पति कृष्णा अभिषेक के सुपरस्टार मामा गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच चल रहे पब्लिक झगड़े के बीच आया है।

बता दें कि अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता अहूजा अपने रिश्ते के बारे में अलग-अलग और तीखे कमेंट्स कर रही हैं। साथ ही, पब्लिक में अभिनेता के छवि खराब कर रहा हैं।

सुनीता अहूजा ने पॉडकास्ट में शादी में बेवफाई को लेकर खुलकर बातें की, जिसमें दावा किया गया है कि गोविंदा के अफेयर्स रहे हैं। कुछ दिन पहले, सुनीता अहूजा ने पैपराजी से बात करते हुए गोविंदा को अपनी नई हीरोइन का 'शुगर डैडी' कहा था, जिसके साथ, सुनीता अहूजा के मुताबिक, उसका अफेयर चल रहा है।

सुनीता अहूजा के चौंकाने वाले दावों ने कई लोगों को हैरान कर दिया है। इस पर, गोविंदा ने कुछ समय पहले रिएक्ट भी किया था। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा था कि सुनीता अहूजा उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही हैं।

उन्होंने उनसे मुख्य रूप से गालीगलौज बंद करने और अपनी गालियों पर थोड़ा कंट्रोल रखने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि उनके साथ एक बहुत छोटी एक्ट्रेस थी, इसका मतलब यह नहीं है कि उनका अफेयर चल रहा है और यह भी कहा कि बॉलीवुड के इतिहास में कई बड़े स्टार्स ने अपने से बहुत कम उम्र की एक्ट्रेस के साथ काम किया है।

40 की उम्र के लोगों की कोई टाइमलाइन नहीं है, बस वाइब्स है : प्रियंका चोपड़ा

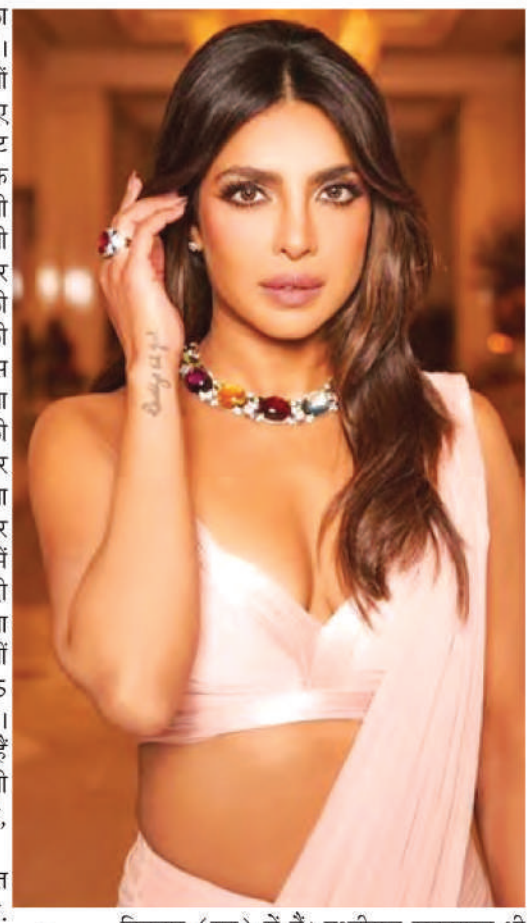

बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा ने 40 की उम्र पार कर ली है। अभिनेत्री ने अपनी उम्र से जुड़े पड़ावों को मजेदार अंदाज में समझाते हुए सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 40 के बाद भी लाइफ फुल ऑन मस्ती और वाइब्स से भरी होती है। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक नोट शेयर किया। इसमें उन्होंने बताया कि 40 की उम्र के लोग कुछ जवां , तो कुछ की मांसपेशियां खींच जाती हैं। कोई इस उम्र में दादी बन जाता है, कोई नया बच्चा पैदा करता है, कोई 20 साल की शादी की सालगिरह मनाता है और कोई यंग लड़के-लड़की को डेट करता है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा द्वारा शेयर किए गए नोट में लिखा, 40 की उम्र में आना बहुत अजीब है, एक दोस्त दादी बन गई है, एक का अभी-अभी बच्चा हुआ है, एक अपनी शादी की 20वीं सालगिरह मना रही है और एक 25 साल के लड़के को डेट कर रही है। हममें से आधे लोग 28 के लगते हैं और आधे लोग सोते-सोते ही मांसपेशी खींच लेते हैं। कोई टाइमलाइन नहीं है, बस वाइब्स हैं।

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की बात करें, तो वे निर्देशक एस.एस. राजामौली की आगामी पैन इंडिया फिल्म 'वाराणसी' से तमिल सिनेमा में डेब्यू करने जा रही हैं। यह फिल्म भारतीय के जरिए वे भारतीय सिनेमा में वापसी भी कर रही हैं। एक्शन-एडवेंचर फिल्म वाराणसी में अभिनेत्री 'मंदाकिनी' नाम की एक मुख्य भूमिका निभा रही हैं और उनके साथ सुपरस्टार महेश बाबू भी मुख्य किरदार (रुद्र) में हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन भी फिल्म में कुंभा नाम के व्यक्ति का अहम रोल निभाते नजर आएंगे।

यह एक समय यात्रा (टाइम-ट्रैवल) और ग्लोबल एक्शन-एडवेंचर फिल्म है, जिसकी कहानी वाराणसी शहर और एक आसन्न संकट के इर्द-गिर्द घूमती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सलमान खान के बड़े फैन निकले ओरी बिस्तर के पास रखता हूं अभिनेता की तस्वीर

मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी इन दिनों लोकप्रिय स्टंट-आधारित रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 15' में नजर आ रहे हैं। शो में ओरी ने मजेदार खुलासा करते हुए बताया कि वे सोते समय सलमान खान की तस्वीर बिस्तर के पास रखते हैं। ओरी का कहना है कि सलमान खान ने उनके करियर के शुरुआती दिनों में मदद की थी। शो के दौरान रोहित शेट्टी ने ओरी से पूछा, ₹मैंने सुना है कि तुम्हें पेंसिल से डर लगता है। डर को लेकर ओरी ने कहा, हां, मुझे डर है कि अगर मैं पेंसिल से लिख रहा हूं और लिखते समय छींक आ गई, तो पेंसिल मेरी नाक में घुस जाएगी, दिमाग तक पहुंच जाएगी और मैं मर जाऊंगा।

ओरी का ये डर सुनकर शो में मौजूद सभी कंटेस्टेंट हंसने लगे। हालांकि, इसके बाद बातचीत एक अलग मोड़ पर चली गई। एक कंटेस्टेंट ने ओरी की पोल खोलते हुए कहा, सर, वह झूठ बोल रहा है। वह अपने बिस्तर के पास सबसे बड़े स्टार, सलमान खान की तस्वीर रखता है। वह पेंसिल से कैसे डर सकता है? इसे लेकर ओरी ने खुलासा करते हुए बताया कि सलमान खान उनके लिए कितने खास हैं। उन्होंने कहा, मैं हर घर में और हर सफर में सलमान खान की फोटो अपने बिस्तर के पास रखता हूं और अगर मेरे आसपास तस्वीर नहीं है, तो मैं सोने से पहले उस चश्मे को लगाता हूं, जिसमें सलमान की तस्वीर दिखे, ताकि मैं उन्हें देख सकूं। रोहित शेट्टी समेत शो के सभी कंटेस्टेंट को इसके पीछे की वजह जानने की उत्सुकता हुई। रोहित शेट्टी ने इसके पीछे की वजह पूछी, तो ओरी ने कहा, उन्होंने मुझे मेरा पहला हिट ब्रेक दिया था, इसलिए मैं यही फोटो हर जगह साथ लेकर जाता हूं।

ओरी के इस बयान से पता चलता है कि न सिर्फ वे सलमान के बड़े फैन हैं बल्कि उनकी फोटो को अपने लिए एक लकी चार्म भी मानते हैं। फिलहाल शो में ओरी मुश्किल स्टंट कर रहे हैं और अपनी एक ऐसी साइड दिखा रहे है जिसकी फैंस को उम्मीद नहीं थी।

एयर होस्टेस से एक्टिंग का सफर, आज बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल

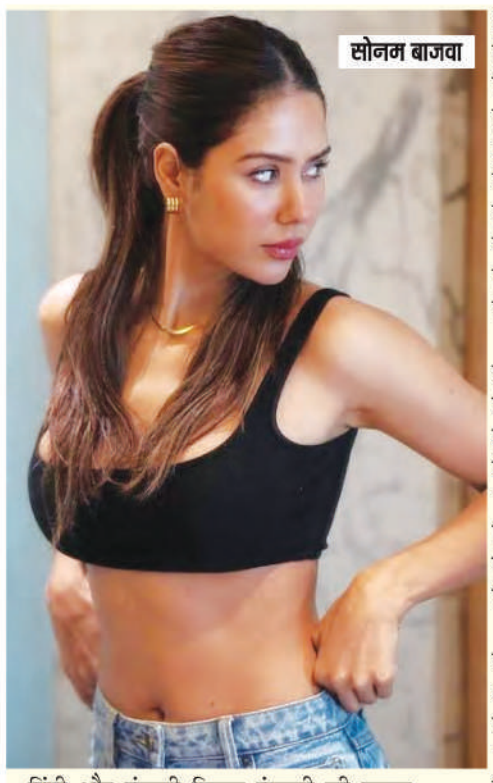

हिंदी और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक सोनम बाजवा आज के समय में एक ऐसा नाम हैं, जो अपनी खूबसूरती के साथ-साथ बेहतरीन एक्टिंग और लाजवाब डांस मूव्स के जरिए लाखों फैंस के दिलों पर राज करती हैं। सोनम बाजवा एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और मॉडल हैं, जो मुख्य रूप से पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। उनका पूरा नाम सोनम प्रीत कौर बाजवा है, जिनका जन्म 16 अगस्त 1989 को रुद्रपुर, उत्तराखंड में हुआ था। उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में पंजाबी फिल्म 'बेस्ट ऑफ लक' से की। सोनम ने अपनी शुरुआती पढ़ाई-लिखाई रुद्रपुर के जेसी पब्लिक स्कूल से पूरी की। इसके बाद वह दिल्ली आ गईं और दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। सोनम को शुरू से ही एक्टिंग में रुचि थी। इसलिए वह मुंबई चली गईं और वर्ष 2012 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में बतौर प्रतिभागी भाग लिया।

सोनम ने अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले कुछ समय के लिए एयर होस्टेस के रूप में भी काम किया, लेकिन उसे छोड़ उन्होंने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने के बाद 'पंजाब 1984', 'सरदार जी 2', 'निक्का जैलदार', 'मंजे बिस्तरे', 'गुड्डियां पटोले' और 'कैरी ऑन जट्टा' जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया।

अभिनेत्री की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जर्नी की बात करें तो उन्होंने बॉलीवुड में कैमियो और कुछ खास प्रोजेक्ट्स के जरिए कदम रखा। इसके अलावा उन्होंने 'बाला' और 'स्ट्रीट डांसर 3डी' में भी विशेष भूमिकाएं निभाईं। फिर अभिनेत्री के करियर में एक ऐसा दौर आया कि उन्होंने इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों के साथ लोकप्रिय फिल्मों में बतौर मुख्य अभिनेत्री काम किया, जिनमें 'हाउसफुल 5' और 'बॉर्डर 2' मूवी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त अभिनेत्री को पंजाबी फिल्म 'अर्दब मुटियारा' में बेहतरीन अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर पीटीसी पंजाबी फिल्म पुरस्कार भी मिला है। वहीं, सोनम बाजवा आज के समय में बॉलीवुड की उभरती हुई शीर्ष अभिनेत्रियों में एक हैं।

'सिनेमा सिर्फ निर्माता का नहीं होता', 'केजीएफ' के निर्माता के बयान का यश ने दिया जवाब

यश अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। वह इसके प्रमोशन में बिजी हैं। हाल ही में कन्नड़ स्टार ने निर्माता अल्लू अरविंद की उस टिप्पणी का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने 'केजीएफ' की सफलता से पहले यश की लोकप्रियता पर सवाल उठाया था। 'केजीएफ' की सफलता ने ही यश को पूरे भारत में एक मशहूर कर दिया।

क्या बोले थे निर्माता?

शो आप की अदालत में यश से उस बयान के बारे में पूछा गया जो निर्माता अल्लू अरविंद ने दिया था। अल्लू अरविंद ने कहा था 'केजीएफ से पहले यश कौन थे? एक निर्माता फिल्म बनाता है और अभिनेता उसमें काम करके फायदा उठाता है।'

क्या बोले यश?

इस बयान पर यश ने कहा 'यह सच है। मगर मेरा यह भी मानना है कि सिनेमा सिर्फ निर्माता का नहीं होता। सिनेमा में बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन क्रेडिट सिर्फ एक्टर को मिलता है। चाहे वह कैरेक्टर आर्टिस्ट हो या लेखक, सिनेमा में हर कोई कड़ी मेहनत करता है, लेकिन अगर एक्टर उसे संभाल नहीं पाता, तो फिल्म नहीं चलेगी।'

यश ने की दर्शकों की तारीफ

'केजीएफ' स्टार ने आगे कहा 'मुझे लगता है कि दर्शक सही होते हैं, कभी-कभी मैं सोचता हूं कि सारा प्यार एक्टर को ही क्यों मिलता है। फिर मुझे एहसास हुआ कि (काम के) दबाव के बावजूद, जब कोई एक्टर फिल्म के जरिए लोगों से जुड़ पाता है और अपनी भावनाएं पहुंचा पाता है, तो वही चीज काम कर जाती है। मेरा सच में मानना है कि दर्शक कभी गलत नहीं होते।'

कब रिलीज होगी 'टॉक्सिक'

यश जल्द ही एक और बड़ी फिल्म 'टॉक्सिक' के लिए तैयारी कर रहे हैं। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत भी नजर आएंगी। यह फिल्म 26 अगस्त, 2026 को रिलीज होगी।

इंडस्ट्री में मैं जनता को खुश करने के लिए आई हूं न कि किसी एक्टर को : काजल राघवानी

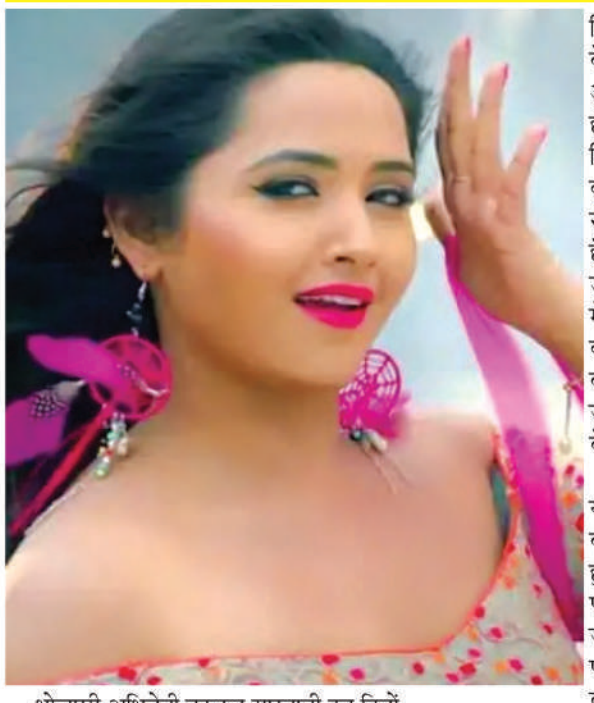

भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी इन दिनों रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' और अपने सोशल मीडिया बयानों के कारण चर्चा में हैं। अभिनेत्री ने सोमवार को फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कलाकारों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कुछ लोग उन्हें झूठा साबित करने पर तुले हुए हैं। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक नोट जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री के 3 लोग उनका काम, टैग और हक छीनने में तुले हुए हैं। अभिनेत्री ने जारी किए गए नोट पर लिखा, सत्य हमेशा सत्य होता है और सत्य को झूठे लोग कुछ समय तक दबा जरूर सकते हैं, लेकिन सत्य को झूठ में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। मैंने जो कहा है सच कहा है और वो सब जानते हैं और जो अपने स्टारडम के दम पर इसे झुठलाना चाहते हैं, मुझे झूठा साबित करने पे तुले हुए हैं 3 लोग मिलके तो सोचिए मेरी बात कितनी सच्ची होगी जिसे आप सब को मिलके झूठा साबित करने के लिए इस लेवल तक जाना पड़ रहा है।

अभिनेत्री ने अपना नोट शेयर करते हुए लिखा, बाप रे ये तो सब में बेस्ट है। लोगो में छीनने की आदत पड़ी है। चाहे काम हो, किसी का हक या फिर, किसी का टैग। अभिनेत्री का कहना है कि वे अपने काम से जनता को अपनाने आई हैं, न की किसी एक्टर को। उन्होंने लिखा, इस इंडस्ट्री में मैं किसी एक्टर को खुश करने के लिए नहीं आई हूं, बल्कि जनता का दिल जीतने के लिए आई हूं और वे ये सब देख ही रहे हैं।

अभिनेत्री दिनेश लाल यादव निरहुआ के द्वारा दिए बयान पर पलटवार करते हुए लिखा, एक कहते हैं कि पत्नी से प्यार नहीं है। जाहिर है क्योंकि उनकी पत्नी के साथ एक वीडियो वायरल हो गया था, तो सफाई भी देनी बनती है। एक प्रचार के लिए पत्नी को अपनाए और फिर छोड़ दिया। आज शो में कह रहे की एक लड़की भाव नहीं दे रही थी तो चार दिन बात नहीं की और फिर आई लव यू बुलवाया। फिर, जय श्री राम। वाह रे सरस्वती पुत्र की जय हो।

गौरतलब है कि अभिनेत्री का यह पोस्ट तब आया, जब भोजपुरी बवाल के हालिया एपिसोड में पवन सिंह, आम्रपाली और दिनेश लाल यादव निरहुला ने काजल राघवानी को घेरा था। हालांकि, शो में काजल राघवानी मौजूद नहीं थी।

काजल राघवानी का यह बवाल रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' पहले एपिसोड से ही देखने को मिला था, जिसमें अभिनेत्री ने अपने पुराने रिश्तों, शारीरिक शोषण, और इंडस्ट्री के अन्य कलाकारों (जैसे पवन सिंह, निरहुआ और आम्रपाली दुबे) पर कई गंभीर खुलासे किए थे, जिसके बाद भोजपुरी सिनेमा में भारी विवाद छिड़ गया है।

मुकेश खन्ना ने किया 'वंदे मातरम' का समर्थन, 'जन गण मन' पर आपत्ति जताते हुए खुद कर गए गलती

अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर 'शक्तिमान' फेम अभिनेता मुकेश खन्ना एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अभिनेता ने कहा कि 'जन गण मन' को हमें

राष्ट्रगान नहीं मानना चाहिए। इसके बजाया हमें 'वंदे मातरम' को बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि, अपने बयान में खन्ना एक गलती कर गाए। जानिए क्या है वह?

क्या बोले मुकेश खन्ना?

मुकेश खन्ना ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, 'मैं तीन साल पहले ये बात बोल चुका हूं कि "वंदे मातरम'को राष्ट्रगीत बनाया जाए। ये 'जन गण मन' हमारा नहीं है। ये क्वीन एलिजाबेथ के जमाने में उनके मान में रवींद्रनाथ टैगोर ने स्तुति गान लिखा था। उसको हमने अपना मान लिया। 'भाग्य विधाता पंजाब सिंह',अरे ये हमारा नहीं है। हमारा है 'वंदे मातरम', जिसे लता जी ने गाया है।'

कहां चूके मुकेश खन्ना?

अपने इस बयान में मुकेश खन्ना ने दो गलतियां कीं। दोनों यहां समझिए...

पहली गलती यह कि अभिनेता ने कहा कि वो तीन साल पहले बोल चुके हैं कि 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगीत बनाया जाए, पर वंदे मातरम तो पहले से ही राष्ट्रगीत है।

दूसरी गलती मुकेश खन्ना ने तब की जब उन्होंने जन गण मन की कुछ पक्तियां बोलकर सुनाईं। उन्होंने कहा- 'भाग्य विधाता पंजाब सिंह'।

खुद भी रिकॉर्ड किया है 'वंदे मातरम'

बातचीत में मुकेश खन्ना ने आगे बताया कि उन्होंने खुद भी 'वंदे मातरम' गाना रिकॉर्ड किया है। इसे वह 6 महीने के अंदर रिलीज करेंगे। उन्होंने कहा, 'मैंने धृष्टता की थी कल्याणजी-आनंद जी भाई के साथ। दो साल हो गए वो गाना पड़ा है मेरे पास। मैंने 7 मिनट का 'वंदे मातरम' गाना रिकॉर्ड किया है, जो आइकॉनिक बन जाएगा। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके 'जन गण मन' को हटाओ और 'वंदे मातरम' को लाओ।'

अपनी बातचीत में आगे एक्टर ने पीएम मोदी की भी तारीफ की और कहा कि उन्हें खुशी है कि वंदे मातरम उठ रहा है।

'मेरे विवाद की वजह से पापा की नौकरी गई' रिया चक्रवर्ती का बड़ा खुलासा

रिया ने बताया कि सुशांत सिंह केस के समय सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उनके विवाद की वजह से उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था।

सरनेम पता चलते ही नौकरी देने से किया इनकार

रिया इन दिनों शो 'ट्रेटर्स 2' में नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस हाल ही में फराह खान के यूट्यूब व्लॉग में पहुंचीं, जहां दोनों ने रिया की जिंदगी के 'चैप्टर 2' को लेकर बातचीत की। इस दौरान रिया ने बताया कि सुशांत की मौत और उसके बाद हुई जांच और गिरफ्तारी के बीच उनके परिवार को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

रिया ने अपने पिता की नौकरी से जुड़ा एक किस्सा शेयर करते हुए कहा, 'पापा को शहर के एक बहुत बड़े अस्पताल में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की बहुत बड़ी नौकरी मिली थी। फिर उन्हें मेरा सरनेम पता चला और उन्होंने कहा, 'सॉरी, आप रिया चक्रवर्ती के पिता हैं, तो आप यहां काम नहीं कर सकते।' रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और मेडिकल कॉर्प्स में एडमिनिस्ट्रेटर और डॉक्टर के तौर पर भी काम कर चुके हैं।

सुशांत की मौत के बाद बदली रिया की जिंदगी

2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया को काफी मीडिया ट्रायल और सोशल बॉयकॉट का सामना करना पड़ा था।

उन्हें जेल भी जाना पड़ा था।

बाद में CBI की क्लोजर रिपोर्ट से रिया को बड़ी राहत मिली।

रिपोर्ट में उन्हें सुशांत की मौत से जुड़े मामले में किसी आरोप के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया।

Printed and Published by **GANTYADA APPARAO** on behalf of **GANTYADA APPARAO**, Printed at Sri Sai Ganga Printers and Publishers Flat No: 504, Bharat Towers, 5th Lane, Dwaraka Nagar, Visakhaptanam, Andhra Pradesh-530016, and Published at H.NO: 38-4-216, MAHARANI STREET, MARRIPALEM, Visakhapatnam, Andhra Pradesh-530018, **Editor: GANTYADA APPARAO.** Mobile : 9059465965, **RNI : APHIN/26/A3657**, editorpenpower@gmail.com